Government has not given an explanation, yet a disclosure has been made about his connections and other things. All I say before I sit down is : Could not Mr. Morarji Desai find anyone else in the country and make him Private Secretary to the Finance Minister and Deputy Prime Minister?

THE BUDGET (BIHAR), 1968-69

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : Sir, I beg to lay on the Table a statement of the estimated receipts and expenditure of the State oi Bihar for the year 1968-69

SUPPLEMENTRY DEMANDS FOR GRANTS FOR EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH FOR THE YEAR 1968-69

SHRI K. C. PANT : Sir, I beg to lay on the Table a statement showing the Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Government of Uttar Pradesh for the year 1968-69.

RESOLUTION RE ACCORDING FULL STATEHOOD TO THE UNION TERRITORY OF HIMACHAL PRADESH — continued.

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : माननीय वाइस चेअरमैन महोदय, मैं उस रोज हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाने के प्रस्ताव पर बोलते हुए यह कह रहा था कि वहां की असेम्बली ने यह प्रस्ताव एकमत से पास किया कि इसको राज्य बनाया जाय। उस सिलसिले में कुछ सदस्यों ने दूसरी इंडियन टेरिटरीज का जिक्र करते हुये कहा कि यह छोटा है या बड़ा है लेकिन मेरी तो राय यही है कि हिमाचल प्रदेश की असेम्बली ने जब प्रस्ताव पास किया कि हिमाचल प्रदेश को राज्य के रूप में परिणत किया जाय तो जो इंडियन टेरीटरी है वह छोटी है या बड़ी है यह देखने की आवश्यकता नहीं है, वहां के अवाम और अवाम के जो प्रतिनिधि हैं, जो नुमाइंदे हैं वह पास करें और खास कर के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करें तो मेरी गुजारिश यह है कि सरकार को उसको मंजूर करना चाहिये, उसमें उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। हमारी सरकार कभी डंडे के सामने, कभी प्रचार के सामने, झुक कर के राज्य बना देती है। राज्य बना, नागालैंड में बना। वहां कोई एक भाषा नहीं, 19 तरह के नागा लोग हैं, उनकी कई डाइलेक्ट्स हैं; उनकी भाषा नागामीज है, आसामी बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन आपने प्रांत का निर्माण किया चूंकि वहां लोगों ने डंडे से अपनी मांग को आपके सामने रखा और आप झुके। तो मेरी गुजारिश है कि आप यह डंडा दूसरे राज्य में चलने न दें। हम मनीपुर जाते हैं, त्रिपुरा जाते हैं। यहां हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि चार जिलें थे अब दस जिले हो गये। वहां के एम० एल० एज० को, वहां के मिनिस्टर्स को क्या सुविधा मिलती है। मिनिस्टर्स को समचुअरी एलाउंस नहीं मिलता। और जब वह देखते हैं कि दूसरी जगह के जो एम० एल०एज० हैं, जो मिनिस्टर्स हैं उनको क्या सुविधा मिलती है तो वह महसूस करते हैं। उनका कहना सही है कि जब पंजाब से, हरियाणा से, केरल से, नागालैंड से उनका रकबा बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, 22 हजार वर्ग मील हो गया, आबादी 30 लाख को हो गई और वहां की असेम्बली ने एक स्वर से यह प्रस्ताव पास कर के केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है कि जल्दी से इसको मंजूर कर के संविधान में तरमीम की जाय और जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाय तो कोई न कोई बहाना ले कर के इसको आप पास नहीं होने देते हैं तो यह मुल्क के लिये और खासकर के डेमोक्रेसी के लिये, जम्हूरियत के लिये, अच्छी चीज नहीं है। मुझको तो अंदेशा है क्योंकि अभी मणिपुर की असेम्बली ने भी पास किया है, उनकी भी अपनी एक मणिपुरी भाषा है हालांकि वह संविधान में लिखी हुई नहीं है जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही उनकी भी एक बहुत पुरानी भाषा है और वहां जो हास्टाइल नागाज हैं वह प्रचार करते हैं कि देखो नागालैंड है लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम क्यों इंडियन टेरिटरी में मिले हुये हो, देखो वहां के लोगों को इतना मिलता है और तुम्हें क्या मिलता है और इस तरह से वहां तीन डिविजनों में उपद्रव कर